प्रकृति और विकास के बीच संतुलन

डॉ रहीस सिंह

ग्लासगो में प्रधानमंत्री द्वारा दुनिया के समक्ष प्रस्तुत यह नवोन्मेषी पहल सही अर्थों में एक नए प्रकार के वैश्वीकरण का संकेत करती है। यह वैश्वीकरण 1990 के दशक के बाजारवादी भूमण्डलीकरण से भिन्न है जिसके मुख्य केन्द्र लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन नहीं बल्कि सबके लिए समान पर्यावरण, समान स्वास्थ्य और समृद्ध जीवनशैली हैं। इसमें 'बाजार की प्रणाली' और 'लाभ का जोड़-घटा' नहीं है बल्कि प्रत्येक को समान प्रकाश और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने की संकल्पना है।

पिछले एक लम्बे कालखंड में दुनिया ने औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रगति की, तो तमाम पुस्तकों से लेकर विवेच्य के अनगिनत साधनों (स्रोतों) तक में इस क्रांति अथवा प्रगति की चर्चाएं हुईं। यह स्वाभाविक भी था कि जिस क्रांति के बल पर नई दुनिया का निर्माण हुआ हो, उसकी वैश्विक बौद्धिक चेतना विकास के उन प्रारूपों में व्याख्या करे जो क्रांति के भौतिक पक्ष के उच्चादर्शों एवं मानकों को स्पर्श करते हैं। कारण यह कि भौतिक प्रगति ही नई दुनिया के विविध कारकों अथवा आयामों को मिलाकर विकास के मानदंड (अथवा संकेतक) सुनिश्चित करती है और उसका अंकगणितीय मूल्य भी। यही कारण है कि अधिकांश देशों और उनके निवासियों की चाहत सही अर्थों में प्रकृति आधारित विकास के साथ खुशी (हैप्पीनेस) की नहीं होती है बल्कि फिजिकल पैरामीटर्स (अथवा इंडीकेटर्स) को छू लेने की होती है जिनका उच्च अंकगणितीय या मौद्रिक मूल्य हो। इसी को समृद्धि का आधार भी मान लिया गया और दुनिया ने इसी दिशा में प्रतियोगिता शुरू कर दी। कई बार ऐसा लगा इन प्रतिमानों को छू लेने या इनसे ऊपर उठ जाने के बाद व्यक्ति स्वयं को उस फ्रेम में फिट करने लगा जिसमें लिखा हुआ था- 'द मैन हू कांकर्ड द वर्ल्ड'। लेकिन जब उसका सामना प्रकृति प्रदत्त आपदाओं से हुआ तो उसके सामने असहाय होने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं दिखा फिर चाहे वह सुनामी हो या कोविड-19 जैसी महामारी। फिर सही क्या माना जाए? विकास के पश्चिमी मॉडल के द्वारा उत्पन्न विभिन्न क्रांतियों को, जिनमें वाणिज्यक क्रांति, औद्योगिक क्रांति से लेकर बाजार और विज्ञापन की क्रांति मनुष्य की संपन्नता का इतिहास लिख रही थीं या फिर भारत की उस सनातन परंपरा के बीच से निकल प्रकृति केन्द्रित विकास के मॉडल को जहाँ मनुष्य और प्रकृति दोनों की खुशहाल, सम्पन्न और धारणीय विकास का प्रतिनिधित्व करते थे। दरअसल नवविकास के मौलिक चिंतन में आर्थिक या वित्तीय लाभ को तरजीह तो दी गयी लेकिन 'नेट डिफिसिट ऑफ नेचर' की अनदेखी होती चली गयी। दूसरे शब्दों में कहें तो विकास की पटकथा में संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र में पैदा हो रहा असंतुलन स्थान ही नहीं पा सका। 1980 के दशक तक यह सुनिश्चित हो गया था कि यदि दुनिया न संभली तो 'नेचर टैक्स' यानी प्राकृतिक कर या प्रकोप की भारी मात्रा मानव जाति को चुकानी होगी। इस पर बुनियादी मंथन प्रारंभ तब प्रारम्भ हुआ जब पूंजीवाद ने बर्लिन की दीवार तोड़कर कम्युनिस्ट सोवियत संघ को ताश के पत्तों की तरह ढहाकर वैश्वीकरण की नई इमारत खड़ी करने की शुरुआत की थी। यही वह समय था जब ब्राजील के रियो डि जेनेरियो में पहली पृथ्वी समिट का आयोजन किया गया था। रियो पृथ्वी समिट से लेकर कॉप 26 तक जलवायु परिवर्तन को लेकर औपचारिक कूटनीतिक मंचन तो होता रहा लेकिन दुनिया किसी ठोस निष्कर्ष तक नहीं पहुँच पाई। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज' (यूएनएफसीसी) के तहत 'कांफ्रेंस ऑफ द पार्टीज' यानी कॉप (सीओपी) मिनिस्ट्रियल स्तर की औपचारिक बैठकें तो करता रहा लेकिन 'स्ट्रैटेजिक एनर्जी पॉलिसीज़' को सही अर्थों में क्रियान्वित नहीं कर सका। इस दिशा में कांप्रिहेंसिव यूनाइटेड ग्लोबल पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की तरफ से हुई जिसका परिणाम इंटरनेशनल सोलर एलायंस। इस एलायंस के तहत दुनिया भारत के नेतृत्व में क्लीन एनर्जी डिप्लोमेसी की तरफ बढ़ी। इसे हम सही अर्थों में ग्लोबलाइजेशन के एक नए युग का आरम्भ कह सकते हैं जो वित्तीय बाजार की दुनिया से प्रकृति और प्राकृतिक ऊर्जा के लिए देशों को एक धरातल पर लाकर ग्लोबल विलेज की अवधारणा का निर्माण करने की कोशिश में है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका सबसे अधिक लाभ विशेषकर विकासशील और अल्प विकसित देशों को होगा और वे शांतिपूर्ण, समावेशी, स्वस्थ और धारणीय या सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ने में कामयाब हो सकेंगे।

दरअसल 'द मैन हू कांकर्ड द वर्ल्ड' से अभिप्रेत विकास की नव परम्परा ने जिस विश्व व्यवस्था का निर्माण किया था उसमें आध्यात्मिक और प्राकृतिक चेतनागत के वे तत्व मौजूद नहीं थे जिनका उद्विकास समय के साथ हुआ था और वे भारत की महान परंपराओं व चेतनाओं

लेखक विदेशी मामलों के विशेषज्ञ हैं। ईमेल: raheessingh@gmail.com

में संरक्षित थे। यही कारण है कि दुनिया यह तक समझ नहीं पायी कि आखिर भूटान जैसा एक छोटा देश जीडीपी के यानी सकल घरेलु उत्पाद के मानदंड से अलग अध्यात्मिक और प्राकृतिक जीवन को सहेज कर दुनिया का सबसे खुशहाल देश कैसे बन गया। या उसने अपने खुशहाली सूचकांक (हैप्पीनेस इंडेक्स) में अध्यात्म और प्रकृति जैसे गैर आर्थिक-गैर बाज़ारवादी विषयों को शामिल क्यों किया। गौर से देखें तो देश के प्राचीन ग्रंथ यजुर्वेद में सृष्टि के समस्त तत्वों से शांति बनाए रखने की प्रार्थना की गई है।

विशेष बात तो यह है कि प्रधानमंत्री ने भारत के प्रकृति मंत्र को उस देश की धरती से आगे ले जाने की संदेश दिया जिसने क़रीब दो सदियों तक दुनिया को आर्थिक साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद तो दिया था लेकिन मानव और प्रकृति के बीच स्थापित सम्बन्धों को खत्म कर दिया था।

लेकिन इस प्रकार की शांति तो तभी संभव हो सकती है जब हम वास्तव में उक्त सभी तत्वों को समझ सकें या दूसरे शब्दों में कहें तो 'असतो मा सद्गमय' तक की यात्रा कर सकें। शायद मनुष्य इसमें पीछे रह गया। लेकिन आज का भारत पुनः यह संदेश दुनिया को देने में सफल हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसे विभिन्न अवसरों पर विभिन्न मंचों से दुनिया के बीच न केवल रखा बल्कि इस पर दुनिया को एक साथ लेकर चलने की युक्तियों को तलाशा और कामयाब भी हुए। विशेष बात तो यह है कि प्रधानमंत्री ने भारत के प्रकृति मंत्र को उस देश की धरती से आगे ले जाने का संदेश दिया जिसने क़रीब दो सदियों तक दुनिया को आर्थिक साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद तो दिया था लेकिन मानव और प्रकृति के बीच स्थापित सम्बन्धों को खत्म कर दिया था। औपनिवेशिक काल के भारतीय इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण देखे जा सकते हैं। उसका उद्देश्य भिन्न था इसलिए वह मानवीय व प्राकृतिक संवेदनाओं से उद्भूत ज्ञान दे भी नहीं सकता था। यह भारत ही कर सकता था, जिसकी एक ठोस शुरुआत हुई प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ग्लासगो (यूनाइटेड किंगडम) से।

यूनाइटेड किंगडम की धरती पर कॉप 26 प्रेसिडेंसी और इंडिया इंटरनेशनल सोलर एलायंस प्रेसिडेंसी के साथ 80 देशों द्वारा समर्थित 'वन सन डिक्लेरेशन' के साथ। इसका उद्देश्य देशों की सीमाओं से परे जाकर सौर ऊर्जा के प्रसार के लिए राजनैतिक नेतृत्व तैयार कर उस पर वैश्विक सहमति और सहकार को एक नया आयाम देना था। बेहतर आपसी सहयोग, साझा क्रॉस बार्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर सिस्टम्स, पावर ट्रेडिंग, ऑपरेशन, टैक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स, फाइनेंसिंग व्यवस्था और साथ मिलकर किए जाने वाली रिसर्च के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसे व्यवहारिक रूप देने के लिए ग्रीन ग्रिड इनीशिएटिव के रूप में 'वन सन, वन वर्ड और वन ग्रिड' निर्णायक कदम साबित होगा। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ने ग्लासगो में सूर्योपनिषद को संदर्भित करते हुए कहा था कि हर चीज सूर्य से पैदा हुई है सूर्य ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है और सौर ऊर्जा सबका ख्याल रख सकती है। लीडर्स इवेंट एक्सीलरेटिंग क्लीन टैक्नोलॉजी इनोवेशन एंड डिवेलपमेंट में उन्होंने कहा था कि हमारी स्पेस एजेंसी इसरो विश्व को एक सोलर केलकुलेटर एप्लीकेशन देने जा रही हैं। इससे सेटेलाइट डेटा के आधार पर विश्व की किसी भी जगह की सौर ऊर्जा क्षमता मापी जा सकेगी। यह एप्लीकेशन सोलर प्रोजेक्ट का लोकेशन तय करने में उपयोगी होगी और इससे 'वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड' को मजबूती मिलेगी। उनका तर्क था कि इस रचनात्मक पहल से कार्बन फुटप्रिंट और ऊर्जा की लागत तो कम होगी ही अलग-अलग क्षेत्रों और देशों के बीच सहयोग का नया मार्ग भी खुलेगा। उन्होंने यह विश्वास भी व्यक्त किया था कि 'वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड' और ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव के सामंजस्य से एक संयुक्त और सुदृढ़ वैश्विक ग्रिड का विकास होगा। 'ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव - वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड' निवेश प्रेरणा की दृष्टि

से महत्वपूर्ण रहेगी जिससे विकास के साथ-साथ रोज़गार के लाखों अवसर भी पैदा होंगे।

ग्लासगो में प्रधानमंत्री द्वारा दुनिया के समक्ष प्रस्तुत यह नवोन्मेषी पहल सही अर्थों में एक नए प्रकार के वैश्वीकरण का संकेत करती है। यह वैश्वीकरण 1990 के दशक के बाजारवादी भूमण्डलीकरण से भिन्न है जिसके मुख्य केन्द्रबिन्दु लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन नहीं बल्कि सबके लिए समान पर्यावरण, समान स्वास्थ्य और समृद्ध जीवनशैली हैं। जहाँ इसमें 'बाजार की प्रणाली' और 'लाभ का जोड़-घटा' नहीं है बल्कि प्रत्येक को समान प्रकाश और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने की संकल्पना है। प्रत्येक व्यक्ति सूर्य द्वारा विकिरित प्रकाश सौर ऊर्जा का समान रूप से बिना किसी भेदभाव के प्रयोग कर सकता है। यही स्थिति राष्ट्रों के संदर्भ में भी लागू होती है। चूंकि इस मामले में कर्क और मकर रेखा के बीच आने वाले देश आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत निर्धन होने के बावजूद धनी हैं। उन्हें सबसे ज्यादा समय तक सूर्य का प्रकार और ऊष्मा मिलती है। इसलिए वे एक प्रकार से 'सौर ऊर्जा' के सबसे बड़े 'हितधारक' (बेनिफिशरी) अथवा लाभांशी (स्टेक होल्डर) हैं। आवश्यकता इस बात की थी कि वे इसका निरंतर, संतुलित और उपयोगवादी इस्तेमाल कर सकें। इस दिशा में प्रधानमंत्री का 'वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड' का यह ग्लोबल फिनामिना निर्णायक साबित होगा। इससे मौसम के परिवर्तन के बावजूद ऊर्जा की संतुलित आपूर्ति निरंतरता पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे बेहतर पहल और वैचारिकी क्या हो सकती है किसके माध्यम से गरीब देश के नागरिक भी आत्मनिर्भर उत्पादक और उपभोक्ता की हैसियत तक पहुँच जाएं। इसका परिणाम यह होगा नागरिकों में स्वतंत्र विकास की चेतना विकसित होगी जो उन्हें संयुक्त रूप से एक देश के रूप में नई विश्व व्यवस्था में नए प्रतिस्पर्धी की हैसियत प्रदान करने में सहयोगी होगी। अगर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के इस पहल को सफलता मिलती है तो दुनिया का एक बड़ा हिस्सा 'ग्रोथ विद ग्रेट इकोलॉजिकल सिस्टम' के साथ आगे बढ़ने और भारत पुनश्च दुनिया को उस भारतीय जीवन पद्धति से परिचित कराने में सफल हो जाएगा जो अभी वेदों, शास्त्रों और पुराणों में देखी या पढ़ी जा सकती है। अब देखना यह है कि दुनिया पूरी प्रतिबद्धता और क्षमता के साथ भारत के नेतृत्व में भारत के साथ कितने कदम आगे बढ़ पाती है।

एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि सौर ऊर्जा की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए केवल एनर्जी ट्रांजिशन की नहीं बल्कि अभूतपूर्व जलवायु सहयोग पर आधारित एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता होगी। इसलिए अभी बहुत सी अड़चने भी आएंगी। इसे पूरा करने के दो प्रमुख पहलू होंगे। प्रथम – टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स का संयोजन। इनके इस्तेमाल से ऐसी इलेक्ट्रिक ग्रिड का निर्माण संभव होगा जो दुनिया भर के लोगों को बड़े पैमाने पर सुरक्षित, विश्वसनीय और सस्ती नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान कर सके। इसके लिए सीमाओं और टाइम ज़ोन को पार करने वाली नई ट्रांसमिशन लाइनों की जरूरत होगी। मिनी-ग्रिड और ऑफ-ग्रिड एनर्जी एक्सेस सोल्यूशंस को भी तेजी से स्केल-अप करना होगा। ज़्यादा सौर ऊर्जा वाले इलाक़ों को महाद्वीपीय स्तर के क्षेत्रीय ग्रिड्स के ज़रिए आपस में जोड़ने की जरूरत होगी और साथ ही इंटर-रीजनल लिंक अलग-अलग टाइम ज़ोन्स को साथ जोड़ने पड़ेंगे ताकि कम सौर ऊर्जा वाले क्षेत्रों को भी विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। सामूहिक या एकीकृत राजनीतिक इच्छाशक्ति इस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा पहलू होगा, जो सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, नीति

अगर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के इस पहल को सफलता मिलती है तो दुनिया का एक बड़ा हिस्सा 'ग्रोथ विद ग्रेट इकोलॉजिकल सिस्टम' के साथ आगे बढ़ने और भारत पुनश्च दुनिया को उस भारतीय जीवन पद्धति से परिचित कराने में सफल हो जाएगा जो अभी वेदों, शास्त्रों और पुराणों में देखी या पढ़ी जा सकती है।

निर्माताओं और मिशन के लिए ज़रूरी संगठनों के कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकता हो।

बहरहाल, भारत ने ग्लासगो में 2070 तक नेट जीरो की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। साथ ही प्रधानमंत्री ने 2030 तक तय किए जाने वाले चार लक्ष्य भी निर्धारित किए थे। इन लक्ष्यों को हासिल करने का अर्थ है कि जल्द ही भारत में ऊर्जा क्षेत्र, कोयला व तेल से अक्षय ऊर्जा की ओर कदम बढ़ा देगा। इसमें भी सौर ऊर्जा की मुख्य भूमिका होगी। इसकी वाहक बनेगी इंटरनेशनल सोलर एलायंस (आइएसए) जिसके गठन की घोषणा 2015 में नई दिल्ली में की गयी थी। उल्लेखनीय है कि इस पहल के पहल चरण में भारत 'इंडियन सोलर ग्रिड' का निर्माण करेगा तत्पश्चात इसे पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से जोड़ने की दिशा में कदम उठाएगा। इसके बाद इसके साथ अफ्रीकी देशों की कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी। इसका परिणाम यह होगा इस ग्रिड से जुड़े देशों में हर समय उनकी जरूरत के अनुरूप सौर ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। आइएसए के अनुमान के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर 2050 तक क़रीब 2,600 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता है। इससे 226 अरब यूरो अथवा लगभग 20 लाख करोड़ रुपये की बचत होगी साथ ही ग्लोबल वार्मिंग को दो डिग्री सेल्सियस से कम पर रोकना संभव हो सकेगा।

वैसे भारत सरकार सौर ऊर्जा का बढ़ावा देने के लिए 30 प्रतिशत तक सहयोग भी कर रही है। कुछ राज्यों में 70 प्रतिशत तक मदद की जा रही है। ध्यान रहे कि ऊर्जा के क्षेत्र को लेकर मुख्य रूप से दो विषय प्रमुख हैं। प्रथम-डिकार्बोनाइजेशन और द्वितीय-बिजली का समान रूप से वितरण। जीवाश्म ईंधन के हानिकारक प्रभावों और लगातार बढ़ते कार्बन उत्सर्जन से पृथ्वी को बचाने की वैश्विक खोज का यह एक हिस्सा है। भारत अभी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और घरों में बिजली पहुँचाने के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है। चूंकि भारत की आबादी अभी भी लगातार बढ़ रही है। इसलिए बिजली की खपत में निरंतर वृद्धि स्वाभाविक है। भविष्य के विकास की संभावनाओं को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि ऊर्जा की मांग अभी और बढ़ती जाएगी। इसलिए यदि भारत को जीडीपी में उत्सर्जन के योगदान को कम करना है, तो उसे क्रांतिकारी स्तर पर कदम उठाने होंगे। भारत को इस दशक के अंत तक अपनी जरूरत का क़रीब 40 प्रतिशत बिजली रिन्यूवेबल स्रोत से पैदा करनी होगी। यह लक्ष्य भारत पहले ही निर्धारित कर भी चुका है। स्वाभाविक तौर पर इस क्षमता को तभी हासिल किया जा सकता है, जब भारत सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करे। इसलिए प्रधानमंत्री का 'ग्रीन ग्रिड पहल' को एकसी अभिनव पहल माना जा सकता है जिस पर स्वस्थ्य, समृद्ध, धारणीय व खुशहाल विकास की बुनियाद टिकी हुई है।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वैश्विक गर्माहट (ग्लोबल वार्मिंग) का स्तर विगत तीस वर्षों में 50 प्रतिशत तक बढ़ चुका है। जीवाश्म ईंधनों के जलाए जाने से कार्बन उत्सर्जन के बढ़ने की गति 62 प्रतिशत के आसपास तक पहुँच चुकी है। यह स्थिति न केवल मनुष्य के लिए बल्कि जैव विविधता के लिए भी खतरा है। यह खतरा मस्तिष्क पर तब और घातक प्रभाव डालता है कि जब प्राचीन सभ्यताओं के पतन की विभीषिकाओं में जैव विविधता की पटकथा से साक्षात्कार कर लेते हैं। आज ठीक उसी प्रकार के उदाहरण देखे जा सकते हैं झीलों, नदियों और तालाबों से सम्बंधित तमाम अध्ययनों में देखा जा सकते हैं। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने दुनिया का ध्यान आकर्षित करते हुए बहुत अच्छी बात कही है। उनका कहना है कि पृथ्वी पर जब से जीवन उत्पन्न हुआ, तभी से सभी प्राणियों का जीवन चक्र, उनकी दिनचर्या सूर्य के उदय और अस्त से जुड़ी रही है। जब तक यह प्राकृतिक कनेक्शन बना रहा तब तक हमारा ग्रह भी स्वस्थ रहा। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्रांति को जीवाशम ईंधन ने ऊर्जा दी थी। जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल से कई देश तो समृद्ध हुए लेकिन हमारी धरती, हमारा पर्यावरण निर्धन हो गए। जीवाश्म ईंधन की होड़ ने भू-राजनीतिक तनाव भी पैदा किए लेकिन आज तकनीक ने हमें एक बेहतरीन विकल्प दिया है।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वैश्विक गर्माहट (ग्लोबल वार्मिंग) का स्तर विगत तीस वर्षों में 50 प्रतिशत तक बढ़ चुका है। जीवाश्म ईंधनों के जलाए जाने से कार्बन उत्सर्जन के बढ़ने की गति 62 प्रतिशत के आसपास तक पहुँच चुकी है। यह स्थिति न केवल मनुष्य के लिए बल्कि जैव विविधता के लिए भी खतरा है।

वास्तव में ईंधन की होड़ ने भू-राजनीतिक तनाव तो पैदा किए हुए हैं। अभी दुनिया के वे ताकतें इसके समाधान खोजने की स्थिति में भी नहीं दिखती जिन्होंने साम्राज्यों के निर्माण से लेकर तमाम संघर्षों, मानवीय चूंकों और ध्वंसों की पटकथाएं लिखी हैं। केवल भारत है जो इस दिशा में बेहतर करने की संकल्पना और मानसिकता रखता है। ऐसे में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 'ग्रीन ग्रिड' पहल भारत की सदियों पुरानी परिकल्पनाओं को ठोस आयाम देकर शांतिपूर्ण, स्वस्थ और समृद्ध विश्व के निर्माण में निर्णायक साबित हो सकती है। ■